NYCS
RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com
दिसंबर 2025, नई दिल्ली

ग्लोबल AI हब बनेगा भारत, नौकरियों की होगी भरमार

अंदर के पन्नों पर

सहकारी समृद्धि के लिए नीति निर्माण एवं नवाचार पर फोकस

युवाओं की ज्यादा भागीदारी से सहकारिता में बढ़ेगा नवाचार

अब युवा बनेंगे सहकारी क्षेत्र के विकास का आधार

IFFCO KISAN DRONE
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
इफको नैनो उर्वरक अपनाएं
अधिक उपज और गुणवत्ता पाएं
इफको की असरदार जोड़ी
नैनो यूरिया प्लस
नैनो डीएपी
नैनो जिंक
नैनो कॉपर
NANO UREA PLUS
NANO DAP
(8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
NANO ZINC
(1.0% Zn w/w)
NANO COPPER
(0.8% Cu w/w)
अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री न. 1800-103-1967
www.iffco.in | www.nanourea.in I www.nanodap.in

युवा सहकार

वर्ष : 02, अंक-06, दिसंबर-2025

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता
दर्शन सोलंकी (विशेष आमंत्रित)
देवेन्द्र सिंह (विशेष आमंत्रित)
रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी (सीईओ)

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं इम्प्रेसन्स प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18-19-20, सेक्टर-59, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

युवाओं को जोड़ने के लिए और उपायों की जरूरत 04

ग्लोबल कोऑपरेटिव में बढ़ा भारत का दबदबा 05

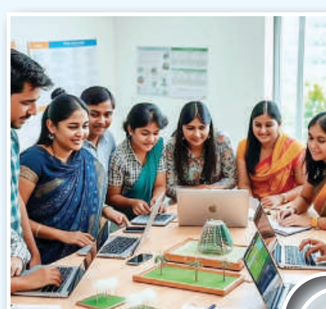

06 अब युवा बनेंगे सहकारी क्षेत्र के विकास का आधार

12 ग्लोबल अकहब बनेगा भारत नौकरियों की होगी भरमार

सहकार सारथी से ग्रामीण सहकारी बैंक और पैक्स बनेंगे आधुनिक 15

कोऑपरेटिव्स की रीढ़ बनी एनसीडीसी 17

सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस बढ़ा रही बनास डेयरी 19

नीति निर्माण एवं नवाचार पर फोकस 22

युवाओं की ज्यादा भागीदारी से सहकारिता में बढ़ेगा नवाचार 26

एनवाईसीएस के इन्वेस्टर मीट का आयोजन 28

भारत के लिए गौरव के साथ चुनौती 29

युवाओं को जोड़ने के लिए और उपायों की जरूरत

युवा सहकार के नवंबर अंक में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के सदस्य और नीति आयोग में संयुक्त सचिव डॉ. कमल कुमार त्रिपाठी का इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था। उस इंटरव्यू में उन्होंने सहकारिता क्षेत्र की कड़वी सच्चाई बताते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही थी, 'आज के युवाओं में सहकार की भावना तो है, लेकिन वे सहकारिता से दूर चले गए हैं।' इस दूरी को पाटने और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सहकारिता से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में कई प्रावधान किए गए हैं। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य तय किया है उसमें सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके लिए युवाओं का सहकारिता क्षेत्र से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं होगा। इसे ध्यान में रखते हुए सहकारिता क्षेत्र की नीतियों और रणनीतियों में व्यापक बदलाव किए गए हैं।

युवाओं में सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पीएमईएसी ने कहा है कि इसके लिए चलने वाले जागरूकता अभियान से पढ़े लिखे 60 प्रतिशत युवाओं को जोड़ा जाए। यह सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि भारत का ज्यादातर शिक्षित युवा अपने करियर को लेकर चिंतित रहता है। सहकारिता में उसे अपना भविष्य नजर नहीं आता है।

इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सरकार को अब कुछ और सुझाव दिए हैं जिसके माध्यम से युवाओं को सहकारिता क्षेत्र की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। ये सुझाव दुनिया के शीर्ष सहकारी संगठन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायांस के पांच ई मॉडल- एजुकेशन, इम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटीज, इंगेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पर आधारित हैं। युवाओं में सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सहकारी समितियों द्वारा आधुनिकीकरण एवं नवाचार अपनाने, युवाओं का प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व बढ़ाने के उपाय करने जैसे सुझाव दिए गए हैं।

अपने सुझाव में पीएमईएसी ने सरकार को कुछ लक्ष्य तय करने के सुझाव दिए हैं। इसके तहत 2030 तक कोऑपरेटिव में युवाओं की भागीदारी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने, युवा नेतृत्व वाली 5,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव का गठन करने और 10 लाख से ज्यादा रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य तय करने की बात कही गई है। युवाओं में सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पीएमईएसी ने कहा है कि इसके लिए चलने वाले जागरूकता अभियान से पढ़े लिखे 60 प्रतिशत युवाओं को जोड़ा जाए। यह सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि भारत का ज्यादातर शिक्षित युवा अपने करियर को लेकर चिंतित रहता है। सहकारिता में उसे अपना भविष्य नजर नहीं आता है। हालांकि, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना से इस कमी को पाटने में मदद मिलेगी और सहकारी क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार होंगे, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा। ऐसे में इन युवाओं को जागरूकता अभियान से जोड़ने के लिए क्या-क्या किए जाएंगे यह समय के गर्त में है और कितने युवा कितने समय में इस अभियान से जुड़ेंगे यह भी देखना होगा और उसी के हिसाब से आगे की रणनीति तय करनी पड़ेगी।

आज के डिजिटल युग को देखते हुए 500 से ज्यादा ऑनलाइन कोऑपरेटिव स्थापित करने जैसे लक्ष्य तय करने का भी पीएमईएसी ने सुझाव दिया है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए केवल कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे युवाओं का भविष्य संवारा जा सकता है, इसे भी देखना पड़ेगा और उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव्स उनके लिए कैसे लाभदायक हैं। सहकारिता राज्य का विषय है। इसलिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों को भी युवाओं को आकर्षित करने के लिए काफी सुधार और मेहनत करने की जरूरत है।

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

ग्लोबल कोऑपरेटिव में बढ़ा भारत का दबदबा

डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव फिर बने आईसीए-एपी के प्रेसीडेंट, निर्विरोध चुने गए

युवा सहकार टीम

फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको के वाइस चेयरमैन डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव लगातार दूसरी बार इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस-एशिया पेसिफिक (आईसीए-एपी) के प्रेसीडेंट चुने गए हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित आईसीए-एपी की 17वीं रीजनल असेंबली में हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में उन्हें इस पद पर निर्विरोध चुना गया। चीन के आदिली बनली और मलेशिया के दातो अब्दुल्ला फतह वाइस प्रेसीडेंट चुने गए हैं।

डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव का फिर से इस संगठन का प्रेसीडेंट चुना जाना भारतीय सहकारिता के विश्व में बढ़ रहे दबदबे के तौर पर देखा जा रहा है। पिछली बार जब वह इस पद के लिए चुने गए थे तब वह पहले भारतीय थे जिन्होंने इसकी कमान संभाली थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए हुए चुनाव में प्रेसीडेंट, दो वाइस प्रेसीडेंट सहित 11 डायरेक्टर चुने गए हैं। सभी का कार्यकाल चार साल का होगा। इस सम्मेलन में नए क्षेत्रीय बोर्ड के चुनाव भी हुए। आईसीए-एपी की अगली क्षेत्रीय बैठक वर्ष 2027 में बीजिंग में होगी। डॉ. यादव ने **युवा सहकार** को बताया कि आईसीए-एपी की रीजनल असेंबली में चर्चा के दौरान भारत की नई सहकारिता नीति की जमकर प्रशंसा की गई। वर्तमान मोदी सरकार में सहकारिता को मिली प्राथमिकता को सभी सदस्यों ने सराहा। चर्चा में कहा गया कि युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की पहल उल्लेखनीय है।

डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव भारतीय सहकारिता क्षेत्र के दिग्गज लीडर हैं। वह करीब दो दशक तक देश की नंबर दो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड जिसे कृभको भी कहा जाता है, के चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा भारतीय सहकारी संस्थाओं के शीर्ष संगठन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी एनसीयूआई के दो बार अध्यक्ष रहे हैं। वे 2010 से 2021 तक आईसीए-एपी के वाइस प्रेसीडेंट भी रहे। वे जर्मनी स्थित अंतरराष्ट्रीय रायफिसेन यूनियन (आईआरयू) और भारत में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ यानी एनसीसीएफ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड, राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण समितियों के संघ नैफकब, राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक संघ नैफस्कब के बोर्ड में डायरेक्टर हैं। उनके नेतृत्व में कृभको और भारतीय सहकारिता ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है।

डॉ. यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बुंदेलखंड, गोरखपुर और लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एमएससी करने के अलावा उन्होंने ज्योग्रॉफी में एमए किया है और बीएड एवं एलएलबी की डिग्री ली है। उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी ली है। वह समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं और 2004 से 2014 तक झांसी लोकसभा सीट के सांसद एवं एक बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं।

इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) दुनिया के 130 देशों के कोऑपरेटिव का शीर्ष संगठन है और आईसीए-एपी इसी का एक हिस्सा है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र का सर्वोच्च सहकारी संगठन है। रीजन असेंबली एक केंद्रीय नीति-निर्माण और प्रतिनिधि निकाय है। यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सभी सदस्य देशों को एक साथ लाता है और उन्हें सहकारी समितियों के विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करने के साथ-साथ पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय गठबंधन बनाने का अवसर प्रदान करता है। ■

अब युवा बनेंगे सहकारी क्षेत्र के विकास का आधार

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने बनायी अधिक से अधिक युवाओं को सहकारी क्षेत्र में लाने की रणनीति

इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायांस के 'पांच ई मॉडल' एजुकेशन, इम्प्लॉयमेंट, इक्वेलिटीज, इंगेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पर होगा काम

युवाओं में जागरूकता बढ़ाना, सहकारी समितियों द्वारा आधुनिकीकरण एवं नवाचार अपनाना, युवाओं का प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व बढ़ाने के होंगे उपाय

अगले पांच वर्ष में युवाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत करने की तैयारी

अभिषेक राजा

नीतिगत मसलों पर व्यापक कदम उठाने के बाद सरकार अब सहकारी क्षेत्र में बड़े बदलाव पर ध्यान केंद्रित करने जा रही है। सरकार का इरादा सहकारी क्षेत्र में कार्यरत मानव संसाधन को वर्तमान जरूरतों के मुताबिक तैयार करने का है। इसके लिए सरकार ने युवाओं पर फोकस करने का निर्णय किया है। अगले पांच साल में सहकारी क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी यह भागीदारी केवल 10 प्रतिशत की है। ऐसा होने से सहकारी समितियां न केवल अपने पारंपरिक ढांचे को तोड़कर अर्थव्यवस्था की मौजूदा जरूरतों के मुताबिक काम करने की स्थिति में आएंगी बल्कि डिजिटल दौर में वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभर रही चुनौतियों का सामना भी कर पाएंगी।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की तरफ से तैयार एक नोट के मुताबिक सहकारिता को देश के विकास की धुरी बनाने के लिए इसमें युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना बेहद आवश्यक है। इसके लिए कोऑपरेटिव

सेक्टर में बड़े बदलाव करना अनिवार्य है। सरकार को सौंपे इस नोट में परिषद ने सुझाव दिया है कि युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ साथ युवा नेतृत्व वाली 5000 से अधिक नई कोऑपरेटिव्स की स्थापना करने की भी आवश्यकता है। परिषद का मानना है कि 10 लाख से ज्यादा रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करना जरूरी होगा। इतना ही नहीं 60 प्रतिशत शिक्षित युवाओं में कोऑपरेटिव के बारे में जागरूकता पैदा करना और 500 से ज्यादा ऑनलाइन कोऑपरेटिव स्थापित करने पर भी फोकस होना चाहिए। परिषद के इन सुझावों पर काम होता है तो सहकारी क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका में आ जाएगा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुताबिक सरकार देश की जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र के योगदान को 30 प्रतिशत तक पहुंचाना चाहती है।

सहकारिता के माध्यम से युवाओं का भविष्य संवारने और उनके लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए-नए अवसर पैदा करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अभी तक देश में सहकारिता का इस्तेमाल केवल व्यक्तिगत अथवा बेहद छोटे समूहों के उत्थान के लिए किया जाता रहा था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसके लिए एक व्यापक विस्तार का मसौदा तैयार किया है। इस बाबत न सिर्फ रोजगारन्मुखी नीतियां बनाई जा रही हैं, बल्कि नए-नए क्षेत्रों में संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बाद सहकारिता क्षेत्र युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का एक बड़ा माध्यम है। हालांकि, सहकारी क्षेत्र में अभी युवाओं की काफी कमी है और ज्यादातर युवा इस क्षेत्र को अपने करियर के रूप में नहीं देखते हैं। खासकर, सहकारी समितियों में नेतृत्व स्तर पर युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए कई पहल की है और युवाओं को इससे जोड़ने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति में प्रावधान किए गए हैं। देश

2030 तक कोऑपरेटिव में युवाओं की भागीदारी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य

5,000 से ज्यादा युवा नेतृत्व वाली कोऑपरेटिव्स की स्थापना

10 लाख से ज्यादा रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करना जरूरी

60 प्रतिशत शिक्षित युवाओं में कोऑपरेटिव के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी

500 से ज्यादा ऑनलाइन कोऑपरेटिव स्थापित करना भी लक्ष्य का हिस्सा

में पहली बार त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से युवाओं को कोऑपरेटिव की शिक्षा एवं प्रशिक्षण को मजबूती मिलेगी। यह यूनिवर्सिटी सहकारी क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी को पूरा करेगी। अमित शाह का मानना है कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी सहकारी क्षेत्र के लिए युवा प्रोफेशनल्स तैयार कर सहकारी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

सरकार की राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के छह स्तंभों में युवाओं को सहकारिता से जोड़ने और सहकारिता के माध्यम से उनका भविष्य संवारने के उपाय किए गए हैं। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि इस बात की संपूर्ण समीक्षा की जाए कि युवाओं को आगे बढ़ाने के क्या उपाय किए गए हैं, कोऑपरेटिव्स की लीडरशिप में उनकी कितनी भूमिका है, सहकारी संस्थाओं के निदेशक मंडल में उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, बोर्ड में शामिल युवा निदेशकों का गवर्नेंस कैसा है, उनके लिए जिम्मेदारी तय की जाती है या नहीं। इस तरह

युवाओं को आकर्षित करने के लिए केवल कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे युवाओं का भविष्य संवारा जा सकता है, इसे भी देखना पड़ेगा और उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव्स उनके लिए कैसे लाभदायक हैं।

सहकारिता राज्य का विषय है। राज्यों को भी इसे बढ़ावा देने के लिए काफी सुधार और मेहनत करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कई राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं है, जबकि अब हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं। एजुकेशन एवं ट्रेनिंग और मानव संसाधन के लिए नीति बनाने, टेक्नोलॉजी को अपनाने जैसे उपाय राज्यों को करने होंगे।

की समीक्षा नहीं की जाएगी तो न तो यह क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा और न ही युवाओं को ज्यादा अवसर मिलेंगे।

भारत युवाओं का देश है। अगर कोऑपरेटिव्स युवाओं को आकर्षित नहीं कर पाएंगे तो देश में रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। सरकार मानती है कि युवाओं को आकर्षित करने के लिए केवल कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से युवाओं का भविष्य भी संवारना है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और संयुक्त सचिव डॉ. कमल कुमार त्रिपाठी ने **युवा सहकार** से कहा, 'यह कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए बहुत नाजुक समय है। आज युवाओं में सहकार की भावना तो है, लेकिन वे सहकारिता क्षेत्र से दूर चले गए हैं। उनको सहकारी सिद्धांतों के माध्यम से इस क्षेत्र में लाना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें समझाना और जागरूक करना होगा कि आखिर यह है क्या और इस क्षेत्र में वे अपना करियर कैसे बना सकते हैं? एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से ही इस क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा कुशल पेशेवरों को तैयार किया जा सकता है। सहकारिता राज्य का विषय है। राज्यों को भी इसे बढ़ावा देने के लिए काफी सुधार और मेहनत करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कई राज्यों में नया कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए मेंबर्स की संख्या 50 तक होना जरूरी है। जम्मू-कश्मीर में तो 100 सदस्यों की अनिवार्यता है। इसी तरह, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा सभी राज्यों में नहीं है, जबकि अब हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं। इस तरह के कई प्रावधानों में राज्य स्तर पर बदलाव की जरूरत है। एजुकेशन एवं ट्रेनिंग और मानव संसाधन के लिए नीति बनाने, टेक्नोलॉजी को अपनाने जैसे उन्हें उपाय करने होंगे।'

कैसे मिलेगा लक्ष्य

सहकारिता क्षेत्र में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए वैश्विक सहकारी संगठन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) ने 'पांच ई मॉडल' को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। ये हैं- एजुकेशन, इम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटीज, इंगेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप।

शिक्षाः युवाओं को सहकारिता क्षेत्र से जोड़ने के लिए सबसे पहले सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। यूनिवर्सिटी का पूरा फोकस सहकारी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, सहकारी क्षेत्र के लिए कुशल पेशेवर तैयार करने के साथ-साथ स्कूल और कॉलेज स्तर पर इसकी पढ़ाई को लेकर सुझाव देने और नीतियां बनाने पर है। इस यूनिवर्सिटी से सहकारी क्षेत्र के लिए युवा एवं योग्य श्रमबल की स्थायी और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी और कौशल संबंधी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए मौजूदा कौशल विकास केंद्रों एवं संस्थानों के साथ तालमेल स्थापित होगा। साथ ही सहकारी क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम व अध्ययन

नई सहकारिता नीति में भी बनाई गई है युवाओं को जोड़ने की रणनीति

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में सहकारी क्षेत्र को पेशेवर, सशक्त और नवाचार की दिशा में आगे ले जाने का खाका प्रस्तुत किया गया है। यह नीति न केवल सहकारी संस्थानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर केंद्रित है, बल्कि इसमें युवाओं को सहकारिता क्षेत्र से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए इस नीति के केंद्र में दो प्रमुख पहल हैं। सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर के एक सर्वोच्च संगठन का निर्माण और सहकारी आंदोलन में युवा पीढ़ी को शामिल करने के लिए एक व्यापक रणनीति। नई नीति के तहत युवाओं को सहकारी उद्यमों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सहकारिता से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल से दक्ष बनाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि युवाओं को सहकारी प्रणाली से जोड़ने और उनके प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक शीर्ष संस्था की स्थापना की जाएगी, जो राज्य स्तरीय सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय कर भविष्य के लिए नेतृत्व तैयार करेगी, जिससे सहकारी संस्थाओं का संचालन अधिक पेशेवर रूप से किया जा सके। यह शीर्ष संस्था पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षक नियुक्ति और मूल्यांकन जैसी व्यवस्थाओं का मानकीकरण करेगी। साथ ही, समाज विज्ञान में डिग्री व डिप्लोमा प्रदान करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को सहकारिता से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखकर देश में पहली बार त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है।

कौशल विकास और नवाचार पर फोकस

इस नीति के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए एक संगठित तंत्र विकसित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित या वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण की व्यवस्था और पहुंच बेहतर हो सके। इसके अलावा, सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही, नए और उभरते क्षेत्रों में सामाजिक उद्यम इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जो ग्रामीण और सामुदायिक स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देंगे।

सहकारी रोजगार के लिए डिजिटल एक्सचेंज

नई नीति में राष्ट्रीय डिजिटल सहकारी रोजगार एक्सचेंज की स्थापना का सुझाव दिया गया है, जो योग्य उम्मीदवारों और सहकारी संस्थाओं के बीच सीधा और पारदर्शी संपर्क सुनिश्चित करेगा। साथ ही, एक राष्ट्रीय शिक्षक और प्रशिक्षक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा, जिससे नियुक्ति की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगी। स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री तैयार करने, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। इसके अलावा, रेफ्रिजरेशन, एक्वाकल्चर, फार्म प्रबंधन जैसे बाजार-उन्मुख कौशलों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरूआत की योजना है।

रिसर्च और फेलोशिप

सहकारी अर्थव्यवस्था, नवाचार और शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में डॉक्टोरल और पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप शुरू करने की योजना भी नई नीति में प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य सहकारी मॉडल पर आधारित अकादमिक शोध को बढ़ावा देना है। इसके तहत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों को सहकारी तंत्र के प्रमुख पहलुओं पर गहन अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सूची तैयार करने के साथ-साथ अनुसंधान और विकास का संचालन भी यही यूनिवर्सिटी करेगी। परिषद ने सुझाव दिया है कि सहकारिता को एक विषय के रूप में स्कूली पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाए। बीए, बीकॉम, एग्रीकल्चर, रिसर्च एवं डेवलपमेंट, पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम आदि में इसे वैकल्पिक विषय के रूप में अपनाया जाए। यूपीएससी एवं राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में सहकारिता को भी एक विषय के रूप में शामिल किया जाए। सहकारिता क्षेत्र की जरूरत के मुताबिक पाठ्यक्रम तैयार

> **युवाओं को सहकारी समितियों की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षा के साथ-साथ उनमें जागरूकता बढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए युवा केंद्रित अभियानों का आयोजन किया जाए। युवा सहकारी नेताओं की सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया, प्रभावशाली व्यक्तियों और कहानी सुनाने के साधनों का उपयोग किया जाए।**

किए जाएं। सहकारिता को पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने के अलावा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कोऑपरेटिव स्टोर, कोऑपरेटिव कैंटीन एवं क्रेडिट सोसायटी बनाई जाए। इससे छात्र न सिर्फ इस क्षेत्र के काम करने के तरीको को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि उनमें सहकार की भावना भी मजबूत होगी।

रोजगारः कोऑपरेटिव के इस व्यापक लक्ष्य को पाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के साथ रोजगारपरक नीतियां भी हों। उचित शिक्षा के बाद युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलेगा तो वह इसे कभी भी करियर के रूप में नहीं अपनाएंगे। यही वजह है कि युवाओं के प्रशिक्षण को भी सरकार महत्वपूर्ण मानती है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ युवाओं को नौकरी सुरक्षित करने और फाइनेंस एवं टैक्स का प्रबंधन करने का प्रशिक्षण भी देना जरूरी है। मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग कोऑपरेटिव में काम करने के लिए तकनीकी दक्षता की जरूरत पड़ती है। परिषद ने सुझाव दिया है कि जहां सामाजिक सुरक्षा कमजोर है, वहां सहायता प्रणाली प्रदान की जाए। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नए कौशल और नई उद्यम गतिविधियों का विकास किया जाए और साझा स्वामित्व एवं सामूहिक सौदेबाजी के विभिन्न रूपों वाले कामगार तैयार किए जाएं। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने, कोऑपरेटिव इनक्यूबेटर की संख्या बढ़ाने, इनोवेटिव इंटरप्रेन्योरशिप की पूंजी तक पहुंच बढ़ाने, उन्हें सहयोगात्मक कानूनी ढांचा मुहैया कराने, समुदाय में व्यापार करने में आसानी हो इसके लिए सहयोग देने जैसे सुझाव दिए गए हैं।

अन्य उपायः युवाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए सहकारी युवा ब्रांड तैयार करने और उन ब्रांडों के साथ युवाओं का जुड़ाव बनाने की भी जरूरत महसूस की गई है। साथ ही युवाओं का नेटवर्क तैयार करने, उनमें स्वामित्व की भावना पैदा करने, उन्हें महत्वपूर्ण नवाचार उपलब्ध कराने, युवा ऊर्जा और अनुभवी एवं प्रतिबद्ध भावी नेताओं का समूह तैयार करने पर भी जोर दिया गया है।

युवा कैसे होंगे आकर्षित

जागरूकता बढ़ानाः युवाओं को सहकारी समितियों की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षा के साथ-साथ उनमें जागरूकता बढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए युवा केंद्रित अभियानों का आयोजन किया जाए। युवा सहकारी नेताओं की सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया, प्रभावशाली व्यक्तियों और कहानी सुनाने के साधनों का उपयोग किया जाए। 'यूथ कोऑपरेटिव एम्बेस्डर' कार्यक्रम बनाएं जाएं और सहकारिता के प्रति जागरूकता एवं रुचि बढ़ाने के लिए इससे जुड़े लोग अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें।

आधुनिकीकरण और नवाचारः सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण, उनके द्वारा नवाचार अपनाए जाने और डिजिटल सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से भी युवा इस ओर आकर्षित होंगे। आईटी, ई-कॉमर्स, नवीकरणीय ऊर्जा या रचनात्मक उद्योगों में युवा नेतृत्व वाले सहकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना भी इसके लिए जरूरी है। आज की डिजिटल दुनिया में डिजिटल टूल्स

को अपनाए बगैर युवाओं को आकर्षित करना मुश्किल है। आज की युवा पीढ़ी को हर चीज ऑनलाइन चाहिए। उनकी इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियां ऑनलाइन सदस्यता प्रणाली, मोबाइल ऐप और ई–गवर्नेंस को अपना कर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ सकती हैं। कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल पर केंद्रित इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं के नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है।

फाइनेंस एवं सपोर्ट सिस्टमः इसके तहत युवा केंद्रित सहकारी ऋण योजनाएं शुरू करने की जरूरत है ताकि युवा नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को स्टार्टअप अनुदान या कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध करवाया जा सके। युवा उद्यमियों का मार्गदर्शन करने के लिए पहले से स्थापित सहकारी समितियां व्यवसाय सलाहकारों के साथ साझेदारी करें ताकि उन्हें परामर्श एवं प्रशिक्षण दिया जा सके। युवा सहकारी समिति शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान और तेज बनाने का भी सुझाव सलाहकार परिषद ने दिया है।

प्रतिनिधित्व और नेतृत्वः कोऑपरेटिव सोसायटीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोऑपरेटिव यूनियन एवं फेडरेशन में युवा प्रतिनिधियों की भागादीरी बढ़ाने के लिए युवाओं की सीट आरक्षित की जाए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सुझाव दिया है कि कोऑपरेटिव यूनियनों में अलग से यूथ विंग की स्थापना की जाए ताकि यूनियनों में युवाओं का इंगेजमेंट बढ़े और उन्हें लीडरशिप ट्रेनिंग मिल सके।

सामाजिक और पर्यावरणीय फोकसः युवाओं को आकर्षित करने के सुझावों में सहकारी समितियों को युवा मूल्यों के साथ तालमेल बिठाने की भी वकालत की गई है। उन्हें स्थिरता, समावेशी और सामुदायिक प्रभाव के मुद्दों पर जोर देने का सुझाव दिया गया है जो युवा पीढ़ी को जोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने कि लिए सहकारी समितियों को स्वच्छ ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था या लैंगिक समानता जैसे सतत विकास लक्ष्यों से निपटना जरूरी है।

कोऑपरेटिव के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कोऑपरेटिव सेक्टर से जोड़ना जरूरी है। युवा न सिर्फ ऊर्जा से भरपूर होते हैं, बल्कि उनके पास नए विचार, आधुनिक एवं नया कौशल, डिजिटल कौशल होता है और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जोश एवं उत्साह भरा रहता है जो किसी भी कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। साथ ही ये सहकारी समितियों की पीढ़ीगत निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं। स्थानीय चुनौतियों से निपटने, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल समावेशन और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने में भी ये मददगार हैं। जोखिम लेने से घबराना नहीं और अनिश्चितताओं के प्रति उनका अलग दृष्टिकोण रखना भी एक महत्वपूर्ण कारक जिसकी वजह से उन्हें कोऑपरेटिव से जोड़ना देश के विकास के लिए लाभदायक साबित होगा।■

कोऑपरेटिव के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कोऑपरेटिव सेक्टर से जोड़ना जरूरी है। युवा न सिर्फ ऊर्जा से भरपूर होते हैं, बल्कि उनके पास नए विचार, आधुनिक एवं नया कौशल, डिजिटल कौशल होता है और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जोश एवं उत्साह भरा रहता है जो किसी भी कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है।

ग्लोबल AI हब बनेगा भारत नौकरियों की होगी भरमार

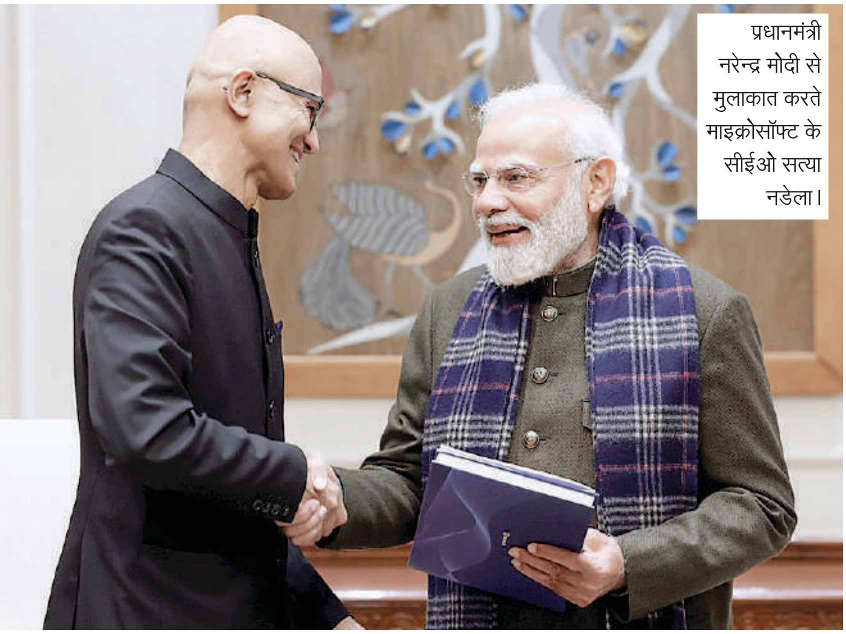

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करते माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला।

माइक्रोसॉफ्ट करेगी 17.5 अरब डॉलर का बड़ा निवेश, हैदराबाद में बनेगा सबसे बड़ा डेटा सेंटर, 1 करोड़ युवाओं को देगी एआई ट्रेनिंग

गूगल ने भी विशाखापत्तनम में एक एडवांस एआई डेटा हब बनाने के लिए 15 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है

युवा सहकार टीम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को इन दिनों पूरी दुनिया में नौकरियां खाने वाले खलनायक के तौर पर देखा जा रहा है। मगर यही क्षेत्र आने वाले वर्षों में नौकरियों की बरसात करेगा, खासकर भारत में, क्योंकि दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही हैं और यहां की डिजिटल एवं इनोवेशन क्षमता पर दांव लगा रही है। अमेरिका की प्रख्यात टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वर्ष 2030 तक भारत में 17.5 अरब डॉलर और गूगल द्वारा 15 अरब डॉलर का बड़ा निवेश करने की घोषणा के साथ ही भारत में ग्लोबल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट का नया युग शुरू होने वाला है। प्रति डॉलर रुपये की मौजूदा कीमत के हिसाब से देखें तो यह निवेश करीब 3 लाख करोड़ रुपये का बैठता है। इंटेल और कॉग्नीजेंट ने भी भारत में निवेश बढ़ाने की घोषणा की है।

ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों के इस भारी भरकम निवेश से भारत में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने, कौशल विकास और अन्य क्षमताएं बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे एडवांस एआई डेटा सेंटर बनाए जाएंगे जो सबसे उन्नत एआई सुविधाओं से लैस होंगे और करोड़ों युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने अकेले 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को एआई सिखाने का लक्ष्य तय किया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और कॉग्निजेंट की इस पहल से यह संकेत मिल रहा है कि भारत अब केवल एक बाजार नहीं रह गया, बल्कि यह दुनिया के एआई और सेमीकंडक्टर परिवर्तन का केंद्र बन रहा है।

दुनिया की इन दिग्गज कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इनमें इंटेल के सीईओ लिप-बू टैन, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार एस और उसकी भारतीय यूनिट के एमडी राजेश वरियर शामिल थे। इस मुलाकात के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने अपने एक्स हैंडल पर भारत में 17.5 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की। यह एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जिससे भारत के एआई-फर्स्ट भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, स्किल बिल्ड क्षमताओं के निर्माण में मदद मिलेगी। इसके तहत माइक्रोसॉफ्ट तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में भारत का अपना सबसे बड़ा डेटा

सेंटर बनाएगी। अभी माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर चेन्नई, मुंबई और पुणे में मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने बताया कि पीएम मोदी से इंडिया में एआई की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई। भारत की महत्वकांक्षाओं में सहयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट एआई के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल पर यह निवेश करेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट की इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि यह नवाचार और प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। सत्या नडेला के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'जब भी एआई की बात आती है दुनिया भारत को आशावादी नजरों से देखती है। सत्या नडेला के साथ काफी सकारात्मक बातचीत हुई है। यह देखकर काफी खुशी हो रही है कि भारत वह देश है जहां माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश कर रही है। भारत के युवा इस अवसर का उपयोग नवाचार करने और बेहतर दुनिया के लिए एआई की शक्ति का लाभ उठाने में करेंगे।'

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हैदराबाद का डेटा सेंटर 2026 के मध्य तक शुरू हो जाएगा। नया डेटा सेंटर डेवलपर्स, सरकारी संस्थानों, शिक्षा संस्थानों, स्टार्टअप्स और उद्यमों की मदद के लिए उन्नत डेटा सुरक्षा, क्लाउड समाधान, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम), प्रोडक्टिविटी टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, 2030 तक कंपनी 1 करोड़ भारतीयों को एआई की ट्रेनिंग देगी। पिछले 10 महीनों में 56 लाख भारतीयों को कंपनी ने एआई की ट्रेनिंग दी है। इसके लिए केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से पार्टनरशिप की गई है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसीडेंट पुनीत चंडोक ने कहा था कि कंपनी एआई आधारित डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में 2026 के बाद भी निवेश करती रहेगी।

माइक्रोसॉफ्ट से पहले गूगल ने विशाखापत्तनम में एक एडवांस एआई डेटा हब बनाने के लिए 15 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। यह निवेश गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट की ओर से किया जाएगा। इस डेटा हब को दुनिया की सबसे उन्नत एआई सुविधाओं में से एक के रूप में डिजाइन किया गया है। यह हब अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा केंद्र होगा। गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने अल्फाबेट डील को कंपनी के ग्लोबल एआई विजन में एक ऐतिहासिक क्षण बताया था जिसके केंद्र में भारत है। विशाखापत्तनम का यह प्रोजेक्ट भारत के डिजिटल भविष्य में दिए जा रहे भरोसे के पैमाने को दशार्ता है।

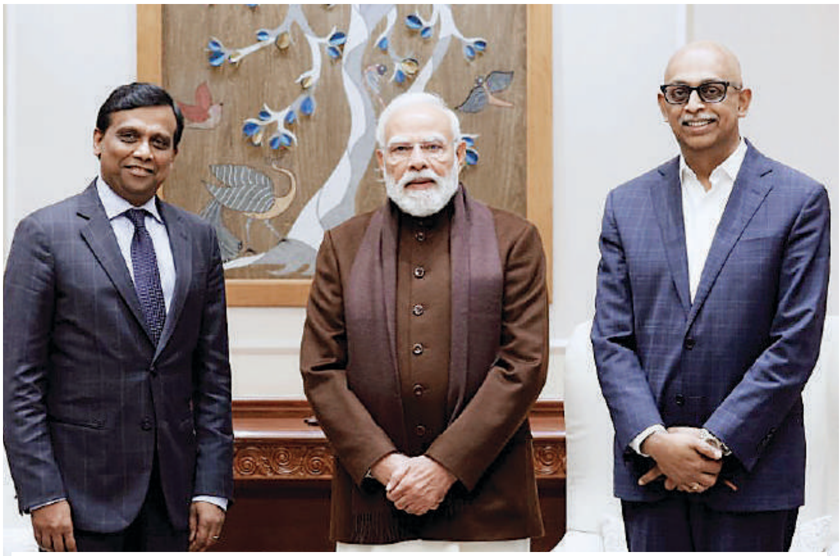

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार एस (बाएं) और एमडी राजेश वरियर (दाएं)

नौकरियों के बनेंगे नए अवसर

इस निवेश से सिर्फ मशीनें और क्लाउड ही नहीं बनेंगे। इससे नए कौशल भी पैदा होंगे। एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई ऑप्स, साइबर सिक्योरिटी समेत सभी क्षेत्रों में मानव संसाधन की भारी मांग बढ़ेगी। क्लाउड, डिजाइन, डिजिटल प्रोसेसिंग और ऑपरेटिंग भूमिकाओं में भी नौकरियां बढ़ेंगी। इसका परिणाम यह होगा कि जितनी ज्यादा नौकरियां एआई के आने से कम होंगी, उससे ज्यादा नौकरियों के

> **जब भी एआई की बात आती है दुनिया भारत को आशावादी नजरों से देखती है। सत्या नडेला के साथ काफी सकारात्मक बातचीत हुई है। यह देखकर काफी खुशी हो रही है कि भारत वह देश है जहां माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश कर रही है। भारत के युवा इस अवसर का उपयोग नवाचार करने और बेहतर दुनिया के लिए एआई की शक्ति का लाभ उठाने में करेंगे।**
>
> **श्री नरेंद्र मोदी**
> **प्रधानमंत्री**

इंटेल के सीईओ लीप-बू टैन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

नए-नए अवसर पैदा होंगे जो युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होंगे। भारत ग्लोबल एआई नौकरियों का सप्लायर बन सकता है।

सेमीकंडक्टर डिजाइन का बड़ा बाजार बना भारत

इंटेल के सीईओ लिप-बू टैन ने पीएम मोदी से मुलाकात को बदलाव की दिशा तय करने वाला बताते हुए कहा कि इंटेल ने देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की और टाटा समूह के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'हमने टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग और भारत के लिए अपार संभावनाओं वाले विविध विषयों पर व्यापक चर्चा की। मैं एक व्यापक सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण नीति लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना करता हूं। इंटेल भारत सेमीकंडक्टर मिशन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।' टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में भारत का उदय ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में निर्णायक कदम है। इंटेल-टाटा सहयोग भारत में इंटेल की ओर से डिजाइन किए गए उत्पादों के निर्माण, कॉम्बिनेशन और पैकेजिंग को सक्षम करेगा, जो ग्लोबल चिप सप्लाई चेन के स्थानीयकरण में एक बड़ी प्रगति है। कॉग्निजेंट ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'हमारे सीईओ रवि कुमार एस और कॉग्निजेंट इंडिया के एमडी राजेश वरियर ने पीएम मोदी से मुलाकात में एआई को अपनाने में तेजी लाने, एआई क्षमताओं और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास को आगे बढ़ाने पर बातचीत की।'

ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों के इस भारी भरकम निवेश से भारत में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने, कौशल विकास और अन्य क्षमताएं बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे एडवांस एआई डेटा सेंटर बनाए जाएंगे जो सबसे उन्नत एआई सुविधाओं से लैस होंगे और करोड़ों युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देंगे।

एआई स्टार्टअप हब बन सकता है भारत

दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियों के भारत में बढ़ते निवेश से यह एक ऐसा देश बन रहा है जो बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल करेगा। इस निवेश का बड़ा हिस्सा डेटा-सेंटर, क्लाउड सर्वर और एआई कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने में जाएगा। इसका मतलब है कि भारत में ही बड़े-बड़े एआई मॉडल की ट्रेनिंग देना, उन्हें डेवलप करना आसान और सस्ता हो जाएगा। अभी तक एडवांस्ड एआई ट्रेनिंग के लिए कंपनियों को अमेरिका और यूरोप के सर्वर पर निर्भर होना पड़ता है। इस निवेश से यह निर्भरता काफी हद तक खत्म होगी।

इसी तरह सस्ते और शक्तिशाली क्लाउड एआई संसाधनों से छोटे व मध्यम स्टार्टअप भी बड़े प्लेयर की तरह एआई प्रोडक्ट बना सकेंगे। फिनटेक, हेल्थटेक, एडटेक, एग्रीटेक, हर सेक्टर में एआई आधारित समाधान तेजी से बढ़ेंगे। इसके अलावा, एआई आधारित कंपनियों की बाढ़ आ सकती है। अगले 4-5 साल में भारत एआई स्टार्टअप हब के रूप में उभर सकता है।

इस तरह के निवेश से भारत में हेल्थ मिशन, नागरिक सेवा पोर्टल, रोजगार, स्किलिंग सिस्टम, कृषि डेटा, न्यायिक प्रक्रियाएं आदि में एआई को तेजी से लागू किया जा सकता है। सरकारी सेवाएं तेज हो सकती हैं और उनमें गलतियों की गुंजाइश कम होगी। साथ ही जब कंप्यूटिंग भारत में होगी, तब एआई मॉडल भारतीय भाषाओं, भारतीय लॉजिक्स, स्थानीय डेटा, स्थानीय बोली एवं व्यवहार और भारतीयों की जरूरत के अनुसार बनाए जा सकेंगे। एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से खेती से लेकर मौसम पूवार्नुमान, फसलों के स्वास्थ्य की जानकारी हासिल करने आदि में एआई को अपनाना आसान हो जाएगा।

सहकार सारथी से ग्रामीण सहकारी बैंक और पैक्स बनेंगे आधुनिक

युवा सहकार टीम

ग्रामीण सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को तकनीकी तौर पर आधुनिक बनाने की पहल के तहत सहकार सारथी की शुरूआत की गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित अर्थ समिट 2025 में इसे लॉन्च किया। इसके तहत 13 से अधिक सेवाएं और प्रॉडक्ट डिजिटल रूप से मिलेंगे। सहकार सारथी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और नाबार्ड की डिजिटल पहल है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण सहकारी बैंकों और पैक्स को तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने, उन्हें डिजिटल युग में लाने और वित्तीय सेवाओं को सुलभ बनाना है।

सहकार सारथी एक एकीकृत तकनीकी प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ग्रामीण सहकारी बैंक और पैक्स डिजी केसीसी, केवाईसी, लोन वितरण, वसूली, अनाज भंडारण योजना के लिए आवेदन और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं दे सकेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी और वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए इसके तहत कैम्पेन सारथी, सारथी वेबसाइट, कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स, शिक्षा सारथी, सारथी टेक्नोलॉजी फोरम को भी शामिल किया गया है। इसे नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है। इसके इस्तेमाल से ग्रामीण सहकारी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की पूरी प्रक्रिया, लोन देने से लेकर वसूली तक का निपटान डिजिटली कर पाएंगे। जबकि ई-पैक्स से पैक्स का डिजिटलीकरण हो जाएगा जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। वह घर बैठे ही पैक्स की सारी सेवाओं का

नाबार्ड द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म सहकार सारथी का केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन

ग्रामीण सहकारी बैंकिंग और पैक्स को डिजिटल रूप से करेगा सशक्त, केसीसी धारकों को मिलेगी विश्वस्तरीय डिजिटल सुविधाएं

ग्रामीण विकास के तीन प्रमुख स्तंभ– कृषि, पशुपालन और सहकारिता लंबे समय तक उपेक्षित रहे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय विकास की धुरी बनाने का ऐतिहासिक परिवर्तन शुरू हुआ। समग्र दृष्टिकोण के साथ हमने तय किया है कि आने वाले वर्षों में देश की प्रत्येक पंचायत में एक सहकारी संस्था स्थापित की जाएगी। सहकारिता के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे और सहकारिता का जीडीपी योगदान वर्तमान की तुलना में बढ़ाया जाएगा।

लाभ उठा सकेंगे। सहकार सारथी के माध्यम से सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की भी सेवाएं ली जा सकेंगी। भारत टैक्सी का अभी ट्रायल रन चल रहा है। उम्मीद है कि जनवरी 2026 में इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग हो जाएगी।

इसी तरह, सहकार सारथी प्लेटफॉर्म पर सहकारी समितियों की रैंकिंग के लिए सूचकांक और सहकारी संस्थाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म वेबसाइट सारथी और कैम्पेन सारथी को इससे जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के आधुनिक तकनीक मिलेगी और वह किसानों और ग्रामीण ग्राहकों को बेहतर ऑनलाइन लोन और लेनदेन जैसी बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। सहकार सारथी ग्रामीण भारत के सहकारी क्षेत्र को डिजिटल बनाने और उसे मजबूत करने के लिए एक व्यापक तकनीकी समाधान है, जो ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, 'तकनीक के बिना सहकारिता आगे नहीं बढ़ सकती। छोटी कोऑपरेटिव्स के पास टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का भार उठाने की क्षमता नहीं थी। नाबार्ड ने 'सहकार सारथी' के माध्यम से सभी ग्रामीण बैंकों को 13 से अधिक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। सभी जिला केंद्रीय, राज्य, कृषि और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक ही टेक्नोलॉजी अम्ब्रेला के अंतर्गत आएंगे, आधुनिक बैंकिंग तकनीक बिना किसी आर्थिक बोझ के उपलब्ध होगी, लोन का वितरण और वसूली, केवाईसी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, अप्रेजल, वेबसाइट निर्माण आदि पूरी तरह टेक-इनेबल होंगे और ग्रामीण सहकारी बैंकों में रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लागू होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से एक मजबूत सहकारी बैंकिंग ढांचा खड़ा किया जा रहा है। जल्द ही ई-केसीसी रखने वाला किसान विश्व के महंगे क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं प्राप्त करेगा।'

अमित शाह ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि भारत को आगे बढ़ना है, तो उसके विकास की परिकल्पना गांवों को केंद्र में रखे बिना संभव नहीं है। ग्रामीण विकास के तीन प्रमुख स्तंभ– कृषि, पशुपालन और सहकारिता लंबे समय तक उपेक्षित रहे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय विकास की धुरी बनाने का ऐतिहासिक परिवर्तन शुरू हुआ। समग्र दृष्टिकोण के साथ हमने तय किया है कि आने वाले वर्षों में देश की प्रत्येक पंचायत में एक सहकारी संस्था स्थापित की जाएगी। सहकारिता के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे और सहकारिता का जीडीपी योगदान वर्तमान की तुलना में बढ़ाया जाएगा। जब यह लक्ष्य पूरे होंगे, तब कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटेगा– चाहे वह पशुपालन करने वाली ग्रामीण महिला हो या छोटे किसान।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तैयार सहकारी डेटा के आधार पर जहां-जहां खालीपन है, वहां विस्तार की योजना बनाई जाएगी। जरूरत वाले गांव और क्षेत्र की पहचान सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुरंत हो सकेगी। पिछले दो वर्षों से चल रहे प्रोजेक्ट में बचे हुए वैज्ञानिक सुधार अगले वर्ष पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात ने डेयरी सेक्टर में पूर्ण सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल स्थापित कर लिया है। उत्पादों का स्वदेशीकरण हो चुका है और लाभ सीधे किसानों को मिल रहा है। अब इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है।

अब लगभग 49 लाख किसान सर्टिफाइड ऑर्गेनिक उत्पाद बना रहे हैं। भारत ऑर्गेनिक्स और अमूल ऑर्गेनिक्स के साथ राष्ट्रीय स्तर की लैब चेन स्थापित हो रही है। 40 से अधिक ऑर्गेनिक खाद्य वस्तुएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि 2035 तक ग्लोबल ऑर्गेनिक मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य है। मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्स किसानों से उत्पाद खरीदकर टेस्टिंग के बाद वैश्विक बाजार में निर्यात करेंगे और इसका लाभ सीधे किसानों के खाते में जाएगा।■

कोऑपरेटिव्स की रीढ़ बनी एनसीडीसी

युवा सहकार टीम

देश भर की सहकारी संस्थाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्र में अलग से सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी समितियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में अभूतपूर्व तेजी आई है। अपनी इस भूमिका से एनसीडीसी सहकारी संस्थाओं की रीढ़ बन चुकी है। वित्त वर्ष 2024-25 में एनसीडीसी ने सहकारी संस्थाओं को करीब 1 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी है। सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में इसे बढ़ाकर सालाना 2 लाख करोड़ रुपये करने का है।

एनसीडीसी की 92वीं महापरिषद की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। एनसीडीसी इस परिवर्तन का प्रमुख आधार बनकर उभरा है। सरकार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से किसानों, ग्रामीण परिवारों, मत्स्यपालकों, छोटे उत्पादकों तथा उद्यमियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सहकारिता देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित एनसीडीसी का कुल वितरण बढ़कर 2024-25 में 95,200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान यह 24,700 करोड़ रुपये था। पिछले चार वर्षों में एनसीडीसी ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और वित्तीय समावेशन, नवाचार और विस्तार के नए आयाम स्थापित किए हैं।

भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सहकारिता एक श्रेष्ठ मॉडल है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी और आजीविका सुनिश्चित करता है। बीते चार वर्षों में एनसीडीसी ने 40 प्रतिशत से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है, शुद्ध एनपीए शून्य रखा है और 807 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है जो अब तक का सर्वाधिक है। इससे संस्था की विश्वसनीयता और साख मजबूत हुई है। एनसीडीसी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों (डीसीसीबी), स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों और स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल एवं मार्केटिंग के क्षेत्र में प्रभावी कार्य किया है।

सहकारी समितियों को सशक्त बनाने तथा उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का मजबूत माध्यम बन कर उभरी एनसीडीसी

पिछले चार वर्षों में एनसीडीसी द्वारा सहकारी संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता लगभग चार गुना बढ़कर 95,200 करोड़ रुपये पर पहुंची

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुगर व डेयरी सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर दिया जोर

मत्स्य क्षेत्र में एनसीडीसी ने 1,070 एफएफपीओ के गठन और सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य पूरा किया है। इसी तरह, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत 2,348 एफएफपीओ को सुदृढ़ करने का कार्य प्रगति पर है। महाराष्ट्र और गुजरात में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए ट्रॉलर (बड़े जहाज) खरीदने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता से ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य समुदाय, विशेषकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण हुआ है।

अमित शाह ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के रूप में पैक्स के लिए किए जा रहे प्रयासों से यह सुनिश्चित हो रहा है कि किसानों को उनकी उपज पर उचित लाभ मिले तथा व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामुदायिक लाभ को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरित क्रांति के बाद जैविक खेती, ऑर्गेनिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएल) और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) जैसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज प्रतिबद्ध हैं।

मत्स्य क्षेत्र में एनसीडीसी ने 1,070 एफएफपीओ के गठन और सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य पूरा किया है। इसी तरह, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत 2,348 एफएफपीओ को सुदृढ़ करने का कार्य प्रगति पर है। महाराष्ट्र और गुजरात में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए ट्रॉलर (बड़े जहाज) खरीदने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता से ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य समुदाय, विशेषकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण हुआ है।

अमित शाह ने कहा कि चीनी व डेयरी सेक्टर में अधिक लाभ के लिए सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा दिए गए 1,000 करोड़ रुपये के अनुदान के आधार पर एनसीडीसी ने 56 चीनी मिलों को एथेनॉल संयंत्र, को-जेन और कार्यशील पूंजी के लिए 10,005 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। इससे चीनी मिलों को वैकल्पिक आय स्रोत और कम दर पर कर्ज प्राप्त हुआ है। इसी तरह, 31 जुलाई, 2025 को सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान को मंजूरी दी। इसके आधार पर एनसीडीसी 20,000 करोड़ रुपये जुटाकर डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, कृषि और महिला सहकारी समितियों को रियायती दरों पर दीर्घकालिक एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा रहा है। साथ ही शहरी सहकारी बैंकों के अंब्रेला संगठन और सहकार सारथी में भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। इससे शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को टेक्नोलॉजी मुहैया कराई जाएंगी।

एनसीडीसी ने सहकारिता आधारित 'भारत टैक्सी' परिवहन सेवा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए नई बहु-राज्य सहकारी समिति का पंजीकरण हो चुका है और ड्राइवर सदस्यता तथा तकनीकी विकास जारी है। एनसीडीसी ने विजयवाड़ा में नया क्षेत्रीय कार्यालय तथा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में उप-कार्यालय स्थापित कर सहकारिता को दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाया है।

युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एनसीडीसी का 'कोऑपरेटिव इंटर्न' कार्यक्रम प्रभावी रूप से संचालित हो रहा है। इसके अंतर्गत चयनित प्रशिक्षु सहकारी संस्थाओं को तकनीकी और प्रबंधकीय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। एनसीडीसी की महापरिषद में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शीर्ष सहकारी समितियों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह परिषद सहकारी विकास, कृषि, ग्रामीण अवसंरचना और संबद्ध क्षेत्रों में वित्त पोषण के लिए नीतियां व दिशा-निर्देश निर्धारित करने वाला सर्वोच्च निकाय है।■

सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस बढ़ा रही बनास डेयरी

युवा सहकार टीम

गुजरात के बनासकांठा स्थित बनास डेयरी ने सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से अपना विस्तार करने और आमदनी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी के तहत इसने वाव-थराद जिले में एक नया बायो सीएनजी और बायो फर्टिलाइजर प्लांट बनाया है जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। बनासकांठा में इसका पहले से एक बायो सीएनजी प्लांट मौजूद है। गोबर धन से कमाई करने के लिए बनास मॉडल पहले से मशहूर है।

सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई भी सामग्री कभी अपशिष्ट नहीं बनती। अपशिष्ट का बेहतर तरीके से निपटान कर उसे विभिन्न रूपों में इस्तेमाल लायक बनाया जाता है और उससे भी कमाई की जाती है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है। डेयरी के मामले में गाय-भैसों का गोबार अपशिष्ट होता है। इसी गोबर का इस्तेमाल बायो गैस और जैविक खाद बनाने में किया जाता है और उससे धन कमाया जाता है।

बनास डेयरी गोबर को बायोगैस और घोल (स्लरी) में बदल रही है। इसके बाद बायोगैस को शुद्ध करके बायो सीबीजी (कंप्रेस्ड बायोगैस) और बायो सीएनजी (कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस) बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। स्लरी को कृषि क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए जैविक खाद में बदला जाता है जिससे पर्यावरण की सुरक्षा होती है और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। कच्ची गैस को कम्प्रेस्ड किया जाता है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसके लिए बनास डेयरी ने बायो सीएनजी पंप भी खोल रखा है।

अमित शाह ने इस अवसर पर कहा, 'बनास डेयरी किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस डेयरी ने बायो सीएनजी प्लांट की जो

बनास डेयरी के बायो सीएनजी व बायो फर्टिलाइजर प्लांट का केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन

डेयरी का कारोबार 24 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा, सर्कुलर इकोनॉमी से 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ेगी डेयरी किसानों की आमदनी

> **देश के सहकारी क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाली डेयरी कोऑपरेटिव अब विकसित होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की मजबूत स्तंभ बन रही है। हमें अब डेयरी के साथ-साथ बायो गैस बनाने की शुरूआत करनी है। समग्र भारत की कोऑपरेटिव डेयरियां अब पशु आहार भी बाजार से नहीं खरीदेंगी, क्योंकि उसे भी कोऑपरेटिव स्तर पर ही बनाया जाएगा। पशु आहार बनाने से जो लाभ होगा, वह भी सीधे दूध उत्पादकों के बैंक खाते में पहुंचेगा।**

परंपरा शुरू की है, वह देश भर की सहकारी समितियों के लिए आदर्श बनेगी और डेयरी उत्पादों, बच्चों के पोषण तथा महिलाओं व किसानों की समृद्धि एवं सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। बायो सीएनजी और जैविक खाद का उत्पादन किसानों की अतिरिक्त आय का मजबूत आधार बनेगा और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और अधिक बढ़ावा देगा।' इस अवसर पर उन्होंने बनास डेयरी के 150 टन के मिल्क पाउडर प्लांट और शिशु आहार प्लांट का शिलान्यास भी किया।

उन्होंने कहा कि देश के सहकारी क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाली डेयरी कोऑपरेटिव अब विकसित होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की मजबूत स्तंभ बन रही है। हमें अब डेयरी के साथ-साथ बायो गैस बनाने की शुरूआत करनी है। समग्र भारत की कोऑपरेटिव डेयरियां अब पशु आहार भी बाजार से नहीं खरीदेंगी, क्योंकि उसे भी कोऑपरेटिव स्तर पर ही बनाया जाएगा। पशु आहार बनाने से जो लाभ होगा, वह भी सीधे दूध उत्पादकों के बैंक खाते में पहुंचेगा। इस पूरी व्यवस्था के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए और यह सब सरकार ने तैयार कर दिया है।

सर्कुलर इकोनॉमी का अभिनव प्रयोग

बनास डेयरी ने कई नई शुरूआत की है। वाव-थराद में अत्याधुनिक प्रोटीन प्लांट एवं हाईटेक ऑटोमैटिक पनीर प्लांट का लोकार्पण भी हुआ। बनास डेयरी ने सर्कुलर इकोनॉमी का अभिनव प्रयोग किया है। सर्कुलर इकोनॉमी से दूध उत्पादकों की आमदनी 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। दूध के बढ़ते उत्पादन से किसानों को जो लाभ होगा, वह अलग रहेगा। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है। इस योजना का केंद्र बनास डेयरी का हेडक्वार्टर ही बनेगा। अमित शाह ने उम्मीद जताई कि बनासकांठा की तरह पूरे देश के पशुपालकों और किसानों की आमदनी बढ़ाने का यह मॉडल सफल होगा।

उन्होंने कहा कि अभी तक अमूल के नेतृत्व में गुजरात की डेयरियां दूध इकट्ठा करती थीं, प्रोडक्ट बनाती थीं, बेचती थीं और जो लाभ होता था, उसे सीधे दूध उत्पादकों के बैंक खाते में डाल देती थीं। अब समय आ गया है कि डेयरी को पूरी तरह सर्कुलर इकोनॉमी बनाया जाए। गाय-भैंस का गोबर बर्बाद न हो और उससे जैविक खाद बने, बायो गैस बने, बिजली बने और उससे जो कमाई हो, वह भी वापस किसानों के पास आए। दुनिया में ऐसे बहुत से हाई-वैल्यू डेयरी प्रॉडक्ट हैं जो अभी भारत में नहीं बन रहे हैं। अमित शाह ने अमूल के चेयरमैन को ऐसी एक पूरी लिस्ट देकर उन प्रॉडक्ट्स के उत्पादन पर काम तुरंत शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन प्रॉडक्ट्स की कीमत बहुत अधिक मिलती है और विश्व बाजार में इनकी भारी मांग भी है। ऐसे में अगर हम सिर्फ दही, घी, पनीर बनाने की बजाय इन 'हाई-वैल्यू प्रॉडक्ट्स' पर ध्यान देंगे, तो हमारे किसान भाइयों-बहनों को कई गुना अधिक लाभ होगा।

बनी एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक डेयरी

बनासकांठा में बनास डेयरी की शुरूआत करने वाले गलबाभाई नानजीभाई पटेल ने जो यात्रा शुरू की थी, वह बढ़ते-बढ़ते इस मुकाम पर पहुंच गई है कि इसका कारोबार 24 हजार

करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। यह एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक डेयरी बन गई है। वर्ष 1960 में वडगाम और पालनपुर तहसीलों के मात्र आठ गांवों की दूध मंडलियों से यह यात्रा शुरू हुई थी। गलबाभाई द्वारा शुरू की गई परंपरा का बहुत सरल मूल मंत्र था कि 'हमारे पास रुपये तो कम हैं, लेकिन हम खूब सारे लोग हैं।' अमित शाह ने कहा कि बहुत सारे लोगों द्वारा थोड़े-थोड़े रुपये इकट्ठा करके बड़ा काम करने का उनका विचार आज एक विशाल वटवृक्ष बन गया है, जो देश ही नहीं, विश्व के सभी सहकारी आंदोलनों को प्रेरणा दे रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए बनास डेयरी ने नौ करोड़ से अधिक 'सीड बॉल्स' और पौधारोपण गतिविधियों का संचालन किया है।

बनास डेयरी ने जो परंपरा खड़ी की है, वह केवल बनासकांठा तक सीमित नहीं रहेगी। यह पूरे देश के करोड़ों पशुपालकों के लिए समृद्धि का माध्यम बनेगी। यह पहल युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार, महिलाओं के लिए स्वरोजगार और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर विकसित भारत की नींव को और सुदृढ़ करेगी।■

बीबीएसएसएल से बीज आलू के लिए एमओयू

सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के विकल्पों को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में बनास डेयरी ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) से बीज आलू के उत्पादन और वितरण को लेकर एक समझौता (एमओयू) किया है। बीबीएसएसएल का मुख्य काम 'भारत बीज' ब्रांड के तहत उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज बनाना, खरीदना और वितरित करना है, ताकि किसानों को समय पर बेहतर बीज मिले, कृषि उत्पादन बढ़े और देश बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। यह पारंपरिक बीजों के संरक्षण, विकास और किसानों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है। केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी की मौजूदगी में बनास डेयरी के प्रबंध निदेशक संग्राम चौधरी और बीबीएसएसएल के प्रबंध निदेशक चेतन जोशी ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू का मकसद है प्रमाणित और रोग मुक्त बीज आलू का उत्पादन करना, वैज्ञानिक खेती के तरीके, अनुबंध खेती और बेहतर बाजार जुड़ाव को बढ़ावा देना है। तकनीकी सुधार और सहकारी प्रयासों को मिलाकर यह पहल फसल की पैदावार बढ़ाने, लागत और नुकसान घटाने तथा आलू उगाने वाले किसानों की आमदनी और स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में सहायक होगी। इस समझौते के तहत बीबीएसएसएल बनास डेयरी की टिश्यू कल्चर और एरोपोनिक सुविधाओं का उपयोग करेगी, जबकि बनास डेयरी तकनीकी और विपणन सहयोग प्रदान करेगी। इस एमओयू पर डॉ. भूटानी ने कहा कि यह साझेदारी मूल्य शृंखलाओं को सशक्त बनाकर तथा उत्पादकता बढ़ाकर किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साझेदारी आलू की खेती के संबंध में 'बीज से बाजार तक' एक व्यापक मूल्य शृंखला बनाएगी।

हर जिले में बनेगी एक डेयरी कोऑपरेटिव

युवा सहकार टीम

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वाव-थराद जिले में स्थित बनास डेयरी में आयोजित सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारिता भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की आय वृद्धि, महिला सशक्तीकरण और देश की दुग्ध आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीन मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज बनाई गई हैं। इनके माध्यम से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी)

और केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जो श्वेत क्रांति 2.0 शुरू की है उसका उद्देश्य है कि हर पंचायत में एक कोऑपरेटिव सोसायटी बने और पर्याप्त दूध उत्पादन होने पर हर जिले में एक डेयरी कोऑपरेटिव स्थापित हो।

उन्होंने कहा कि आणंद में स्थापित त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी दुग्ध प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ साझेदारी कर बीएससी और एमएससी स्तर पर डेयरी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन का पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगी। इन विषयों के ग्रेजुएट अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद देशभर के जिलों में बनास डेयरी के मॉडल को लागू करने में अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके दूध का पूरा लाभ मिले, इसके लिए इस प्रयास को सफल बनाना होगा।

सहकारिता मंत्री ने बनास डेयरी का उदाहरण देते हुए कहा कि देशभर के प्रत्येक जिले में चार अत्याधुनिक सॉइल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी, ताकि किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन मिल सके। किसानों के लिए यह समझाना आवश्यक है कि कब कौन से खाद का उपयोग करना उपयुक्त है, ताकि मिट्टी स्वस्थ रहे और फसल उत्पादकता बढ़े।■

सहकारी समृद्धि के लिए

नीति निर्माण एवं नवाचार पर फोकस

आईसीए-एपी की 17वीं रीजनल असेंबली ग्लोबल कोऑपरेटिव के भविष्य को आकार देने वाला निर्णायक मंच हुआ साबित

कोलंबो में आयोजित सहकारिता के इस वैश्विक संगम में एनवाईसीएस की भी रही मजबूत मौजूदगी

युवा सहकार टीम

श्रीलंका की राजधानी कोलंबो 24-28 नवंबर के दौरान सहकारिता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का केंद्र बनी। इस दौरान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस-एशिया पेसिफिक (आईसीए-एपी) की 17वीं रीजनल असेंबली और 12वें एशिया-पेसिफिक कोऑपरेटिव फोरम का आयोजन हुआ। इसकी मेजबानी श्रीलंका की राष्ट्रीय सहकारी समिति (एनसीसीएसएल) ने की थी। इस सम्मेलन में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 22 देशों के 450 से अधिक सहकारी नेता, विशेषज्ञ, नीति-निमार्ता, शिक्षाविद, युवा प्रतिनिधि और विकास संगठनों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। भारत की ओर से इफको, कृभको, यूथ कोऑपरेटिव का प्रतिनिधित्व करने वाली कोऑपरेटिव सोसायटी एनवाईसीएस सहित केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधिकारी एवं अन्य सहकारी नेता शामिल हुए।

यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर सहकारिता के भविष्य को आकार देने वाला एक निर्णायक मंच था। आईसीए-एपी की रीजनल असेंबली में इस बार चर्चा के केंद्र में सहकारिता और सतत विकास, डिजिटल परिवर्तन, युवा नेतृत्व और युवा सहकारिता मॉडल, महिला सशक्तीकरण में सहकारिता की भूमिका, सहकारी वित्त और माइक्रो-क्रेडिट, जलवायु परिवर्तन और हरित सहकारिता समाधान विषय प्रमुख रहे। सम्मेलन का थीम 'सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं- लचीलापन को मजबूत करना, निवेश को बनाए रखना और स्मार्ट' थी। इंटरनेशनल

आईसीए-एपी यूथ कमेटी के वाइस प्रेसीडेंट बने एनवाईसीएस के अभिषेक कुमार

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) के महाप्रबंधक अभिषेक कुमार को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस–एशिया पेसिफिक (आईसीए–एपी) की यूथ कमेटी का वाइस प्रेसीडेंट चुना गया है। यह चुनाव न सिर्फ एनवाईसीएस के लिए बड़ी उपलब्धि है, बल्कि इसने भारत के सहकारी युवा नेतृत्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है।

आईसीए–एपी के प्रेसीडेंट डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव के साथ अभिषेक कुमार (बाएं)

अभिषेक कुमार लंबे समय से सहकारिता व कौशल विकास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वह हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें सही अवसर देने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करते रहे हैं। युवा शक्ति को संगठित करके सहकारिता को मजबूत बनाना उनका मुख्य लक्ष्य रहा है। उनके प्रयासों ने हजारों युवाओं को नेतृत्व, टीमवर्क और सामाजिक जिम्मेदारी का महत्व समझाया है।

आईसीए–एपी यूथ कमेटी का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में सहकारी संगठनों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, नई सोच लाना और देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। इस समिति के वाइस प्रेसीडेंट के रूप में चुना जाना उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान की बात है। अभिषेक अब विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों, संगठनों और युवाओं के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि सहयोग और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।

वाइस प्रेसीडेंट पद के लिए जॉर्डन, ईरान और भारत से कुल तीन सशक्त उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में अभिषेक सबसे ज्यादा वोटों के साथ विजयी घोषित हुए। यह न केवल एनवाईसीएस के लिए, बल्कि भारत के सहकारिता आंदोलन के लिए भी अत्यंत सम्मानजनक उपलब्धि है। इस उपलब्धि के साथ यह साबित होता है कि भारत के युवा अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। अभिषेक कुमार का चयन भारत के उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सहकारिता के माध्यम से समाज को नई दिशा देना चाहते हैं। उनके नेतृत्व से उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी युवा सहकारिता आंदोलन से जुड़ेंगे, अपने विचार साझा करेंगे और बड़े बदलावों का हिस्सा बनेंगे। यह उपलब्धि उनकी मेहनत और समर्पण की पहचान ही नहीं है, बल्कि एनवाईसीएस की निरंतर प्रगति और भारत की मजबूत सहकारी सोच का संदेश भी देती है।

कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) दुनिया के 130 देशों के कोऑपरेटिव्स का शीर्ष संगठन है और आईसीए–एपी इसी का एक हिस्सा है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र का सर्वोच्च सहकारी संगठन है।

सहकारी पूंजी सुधारों की जरूरत

रीजनल असेंबली में विभिन्न सत्रों के माध्यम से सहकारी आंदोलन के भविष्य को आकार देने पर जोर दिया गया। 'सहकारी पूंजी की समस्या का समाधान मजबूत वित्त पोषण

टीके किशोर बने आईसीएई के वाइस प्रेसीडेंट

आईसीए-एपी के सम्मेलन में केरल स्थित उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति (यूएलसीसीएस) के प्रतिनिधि टीके किशोर कुमार को आईसीए-एपी के कृषि और पर्यावरण समिति (आईसीएई) का वाइस प्रेसीडेंट चुना गया है। वह इस पद को संभालने वाले पहले मलयाली हैं। किशोर कुमार वर्तमान में यूएलसीसीएस के मुख्य परियोजना समन्वयक हैं। चुनाव में प्रो. मां दातो अब्दुल रहमान अब्दुल रजाक शेख को इस समिति का नया प्रेसीडेंट चुना गया। यह समिति सतत कृषि, किसानों की आय, कृषि सहकारी संस्थाओं की मजबूती और जलवायु परिवर्तन से निपटने पर काम करती है।

किशोर कुमार राष्ट्रीय श्रम सहकारी संघ (एनएलसीएफ) के निदेशक भी हैं, जो देशभर में 47,000 से अधिक श्रम सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करता है। वह केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की कई राष्ट्रीय सलाहकार समितियों में यूएलसीसीएस का प्रतिनिधित्व करते हैं और सहकारी क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने वाली पहलों में योगदान दे रहे हैं।

भारत का सहकारी क्षेत्र एक ऐतिहासिक मोड़ पर है, जहां सहकारिता मंत्रालय और नाबार्ड एवं एनसीडीसी जैसी संस्थाएं अभूतपूर्व अवसर प्रदान कर रही हैं।

के साथ' विषय पर आयोजित सत्र में विशेषज्ञों ने सहकारी पूंजी को मजबूत बनाने के लिए कई नए विचार साझा किए। इस सत्र की अध्यक्षता आईसीए-एपी के क्षेत्रीय निदेशक बालासुब्रमणियन अय्यर ने की। इस सत्र में सहकारी क्षेत्र की बदलती वित्तीय जरूरतों को समझने और उनका समाधान निकालने पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने यह महसूस किया गया कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सहकारिताओं को टिकाऊ, प्रतिस्पर्धी और समावेशी बने रहने के लिए नवाचारी वित्तपोषण मॉडल अपनाने और नीति सुधारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

भारत के वरिष्ठ सहकार नेता सतीश मराठे ने 'भारत में सहकारिताओं द्वारा पूंजी और दीर्घकालिक निधि जुटाने के साधन' विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा, 'भारत का सहकारी क्षेत्र एक ऐतिहासिक मोड़ पर है, जहां सहकारिता मंत्रालय और नाबार्ड एवं एनसीडीसी जैसी संस्थाएं अभूतपूर्व अवसर प्रदान कर रही हैं।' अपनी प्रस्तुति में उन्होंने भारत के कानूनी और नियामक ढांचे को समझाया। उन्होंने विश्व के सफल सहकारी मॉडलों का भी उदाहरण दिया जिनमें मिश्रित पूंजी संरचनाएं अपनाई गई हैं। भारत में पूंजी जुटाने के वर्तमान साधनों जैसे सदस्य शेयर पूंजी, नाबार्ड और एनसीडीसी के फंडिंग चैनल, सिडबी व आवासीय वित्त संस्थानों की सहायता, दीर्घकालिक उधार, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट आदि के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। साथ ही भारत की सहकारी पूंजी व्यवस्था में मौजूद प्रमुख कमजोरियों को भी उजागर किया और सुधार के कई सुझाव दिए। इनमें गैर-मताधिकार शेयर की अनुमति, सहकारी बांड जारी करना, भागीदारी आधारित इक्विटी अपनाना, टियर-1 और टियर-2 जैसी हाइब्रिड पूंजी उपकरण विकसित करना और दीर्घकालिक इक्विटी सहायता के लिए राष्ट्रीय सहकारी निवेश कोष बनाना शामिल हैं। सतीश मराठे ने डिजिटल एमआईएस सिस्टम, मजबूत जोखिम प्रबंधन, शासन सुधार के माध्यम से क्षमता निर्माण की जरूरत पर भी जोर दिया।

नवाचार बदलेगा किसानों का भविष्य

बेहतर भविष्य के लिए सहकारिता एक उत्प्रेरक विषय पर आयोजित प्लेनरी सेशन

को संबोधित करते हुए इफोको के एमडी केजे पटेलन ने कहा कि सहकारी संस्थाएं न सिर्फ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देती हैं, बल्कि वैश्विक कल्याण में भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। बढ़ती खाद्य मांग और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच कृषि में नवाचार अब विकल्प नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। पटेल ने इफको द्वारा विकसित नई तकनीकों- खासकर नैनो फर्टिलाइजर का उल्लेख किया, जो किसानों को लाभ पहुंचाने, मिट्टी की उर्वरता बचाने और जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सहायक हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी मॉडल ही वह रास्ता है, जो प्रकृति की रक्षा करते हुए साझा समृद्धि वाला भविष्य तैयार कर सकता है।

प्रगतिशील नीति से सहकारी समृद्धि

'प्रगतिशील नीति के माध्यम से सहकारी समृद्धि का निर्माण' सत्र में एशिया-पेसिफिक में सक्षम नीति वातावरण बनाने पर चर्चा हुई। सहकारी संस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, सदस्यों के कल्याण को सुदृढ़ करने और एशिया-पेसिफिक क्षेत्र में सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए ठोस नीति निर्माण पर इस सत्र में जोर दिया गया। इस सत्र की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल की लेक्चरर प्रो. एन. एप्स ने की, जिन्होंने सहकारी संस्थाओं में लचीलापन बढ़ाने और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों पर मार्गदर्शन किया। इस सत्र को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं एनसीडीसी के एमडी पंकज कुमार बंसल, जॉर्डन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन (जेसीसी) के महानिदेशक अब्देल फताह अल-शलाबी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के अध्यक्ष उपली हेरथ ने भी संबोधित किया।

सहाकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, यह केवल नारा नहीं, बल्कि सहकारिता का दर्शन और भविष्य की दिशा है।

इसका अर्थ है कि ऐसी दुनिया बनाई जाए जहां निर्णय सामूहिक हों, लाभ सामूहिक हो, और विकास समावेशी हो। सहकारिता लाभ के लिए नहीं, बल्कि समुदाय के लिए काम करती है। यह लोकतांत्रिक भागीदारी पर आधारित है। यह समान अवसर और साझा विकास को प्रोत्साहित करती है। आज जब विश्व असमानता, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, सहकारिता ही वह मॉडल है जो सामूहिक समाधान दर्शाती है। आईसीए-एपी की रीजनल असेंबली और एशिया-पेसिफिक फोरम ने यह सिद्ध किया कि सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की संस्था है। इस सम्मेलन में एनवाईसीएस की भागीदारी भारत के सहकारी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह आने वाले समय में साझा नेतृत्व, नवाचार, वैश्विक साझेदारी और युवा सशक्तीकरण के नए अध्याय खोलेगी। सहकारिता के माध्यम से एक बेहतर, न्यायपूर्ण और समावेशी दुनिया का निर्माण हो, यही इस सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश रहा।■

आईसीए-एपी की रीजनल असेंबली और एशिया-पेसिफिक फोरम ने यह सिद्ध किया कि सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की संस्था है। इस सम्मेलन में एनवाईसीएस की भागीदारी भारत के सहकारी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

युवाओं की ज्यादा भागीदारी से

अभिषेक कुमार

महाप्रबंधक, एनवाईसीएस

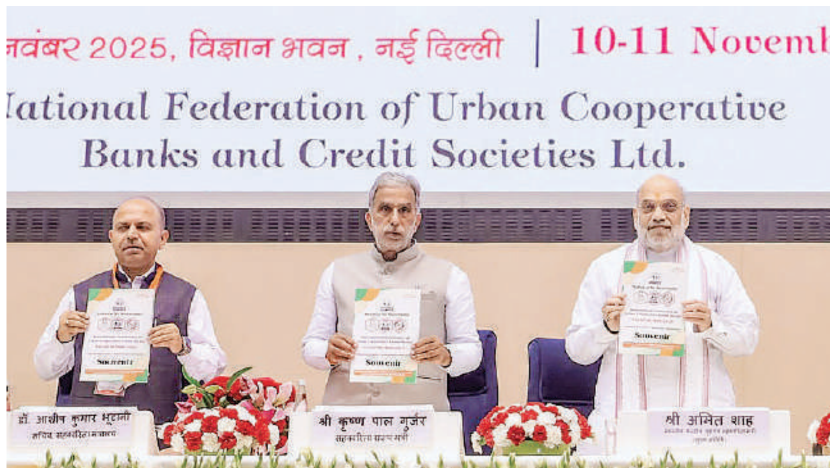

सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से जिस तरह से सहकारिता क्षेत्र में व्यापक बदलाव का दौर शुरू हुआ है, उससे इस क्षेत्र में युवाओं के लिए नए-नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भारत की बड़ी युवा आबादी के लिए इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं में से एक है कोऑपरेटिव बैंकिंग और फाइनेंस का सेक्टर। देश में इस समय हजारों कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसायटी हैं जिनका विस्तार ग्रामीण स्तर से लेकर बड़े शहरों तक है। कोऑपरेटिव बैंकिंग एवं फाइनेंस सेक्टर का अगर संयुक्त रूप से आकलन किया जाए तो यह निजी बैंकिंग क्षेत्र के मुकाबले काफी बड़ा है और इसका विस्तार भी ज्यादा है, लेकिन तकनीक और आधुनिकीकरण के अभाव में निजी बैंकिंग क्षेत्र की तुलना में इसका प्रभाव और ग्राहक आधार कम है।

कोऑपरेटिव बैंकों और क्रेडिट सोसायटियों को भी अब आधुनिक बनाया जा रहा है, उन्हें तकनीकी तौर पर मजबूत और उनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 10 और 11 नवंबर को नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को-ऑप कुंभ 2025 का आयोजन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अंब्रेला संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड (नैफकब) ने किया। देश और विदेश के सहकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया जिसका उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इस सम्मेलन का थीम 'डिजिटलाइजिंग ड्रिम्स-सशक्त समुदाय' रखा गया था। को-ऑप कुंभ 2025 के दौरान पॉलिसी, तकनीक और इनोवेशन के विषय पर इस क्षेत्र से जुड़ी कई संभावनाओं का दोहन करने लिए विचार किया गया। साथ ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के विस्तार का रोडमैप तैयार करने के लिए 'दिल्ली घोषणा 2025' को प्रस्तुत किया गया।

भारत में सहकारिता आंदोलन अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां युवा केवल सदस्य नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता, निर्णयकर्ता और नवप्रवर्तक बनकर उभर रहे हैं। सहकारिता केवल सहयोग नहीं, बल्कि विश्वास, पारदर्शिता और साझेदारी की संस्कृति है। सहकारी संस्थाएं लोगों को स्व-रोजगार और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। इससे व्यक्ति और समुदाय दोनों आत्मनिर्भर बनते हैं। एनवाईसीएस युवाओं की ऊर्जा, विचारों और नेतृत्व क्षमता को एक संरचित दिशा देने के लिए लगातार काम कर रही है। संगठन का मुख्य उद्देश्य सहकारिता को आधुनिक दृष्टिकोण और युवाओं की पहल के साथ जोड़ना है। सहकारिता भारतीय आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ है, लेकिन भविष्य में इसे और सशक्त बनाने के लिए युवा दृष्टि, तकनीक, नवाचार और नेतृत्व अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए इन बिंदुओं पर काम करने की जरूरत है:

डिजिटल सहकारिता: डिजिटल दुनिया के इस दौर में सहकारी संस्थाओं के डिजिटलाइजेशन के बिना युवाओं को इनसे जोड़ना मुश्किल है क्योंकि आज प्रत्येक युवा के हाथ में मोबाइल फोन है और वे कागजी दुनिया की बजाय डिजिटल माध्यम पर ज्यादा निर्भर हैं। ऐसे में सहकारी संस्थाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म, फिनटेक, डेटा प्रबंधन एवं तकनीक का उपयोग कर और डिजिटल सहकारिता के माध्यम से खुद को आधुनिक बनाने की जरूरत है। इस कड़ी में नैफकब ने कोऑपरेटिव सेक्टर में पहली बार पेमेंट और लोन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजीपे ऐप और डिजी लोन ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से कोऑपरेटिव संस्थाओं और उनके सदस्यों को डिजिटली पेमेंट करने और बिना कागजी कार्रवाई के लोन लेने में मदद तो मिलेगी ही, युवाओं के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। इस ऐप से सिर्फ शहरी ही नहीं, दूरदराज के छोटे कोऑपरेटिव

सहकारिता में बढ़ेगा नवाचार

बैंकों और उनके ग्राहकों को भी सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रम सहकारी संस्थाएं लोगों को स्व-रोजगार और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। इससे व्यक्ति और समुदाय दोनों आत्मनिर्भर बनते हैं। सहकारिता के माध्यम से युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल जरूरी है। इससे युवाओं में सहकार की भावना तो मजबूत होगी ही, वे इस क्षेत्र की ओर आकर्षित भी होंगे।

स्टार्टअप-कोऑपरेटिव मॉडलः नवाचार आधारित सहकारी व्यवसायों को प्रोत्साहन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कोऑपरेटिव बैंकों और क्रेडिट सोसायटी को ऐसे व्यवसायों के लिए अलग से स्कीम लाकर उन्हें समर्थन देने की जरूरत है।

सामुदायिक नेतृत्व और युवा भागीदारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक विकास की दिशा तय करने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहकारिता का मूल सिद्धांत यही है कि जब लोग मिलकर सोचते और कार्य करते हैं, तो परिणाम अधिक प्रभावी, संतुलित और टिकाऊ होते हैं। अकेले किए गए प्रयास सीमित रह जाते हैं, जबकि सामूहिक नेतृत्व और संयुक्त प्रयास से विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है। युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और दृष्टि सहकारिता आंदोलन में नई शक्ति का संचार करती है, जिससे समुदाय का सर्वांगीण विकास संभव होता है। अभी सहकारिता क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी मात्र 10 प्रतिशत है जिसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की जरूरत है। तभी सहकारिता आंदोलन में नई ऊर्जा, नवाचार और स्थायी विकास संभव हो पाएगा। नेतृत्व स्तर पर तो युवाओं की भागीदारी नाममात्र है। कोऑपरेटिव सोसायटीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सहित अन्य पदों के लिए होने वाले चुनाव में युवाओं के लिए सीट आरक्षित कर और चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के लिए उम्र सीमा तय कर युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। यह समय की मांग भी है और जरूरत भी।

युवाओं की सहकारी समितियों को वित्तीय सहयोगः सहकारिता आंदोलन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं की सहकारी समितियों का गठन ज्यादा से ज्यादा किए जाने की जरूरत है। साथ ही कम ब्याज दर वाले ऋण, अनुदान कार्यक्रम और निवेश के माध्यम से युवाओं की सहकारी पहल को मजबूत आधार प्रदान किया जा सकता है।

को-ऑप कुंभ जैसे मंच न केवल विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि यह युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने का अवसर भी देते हैं। भारत का युवा सहकारी क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए तैयार है, जरूरत है उन्हें उचित समर्थन और प्रोत्साहन की।■

अभी सहकारिता क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी मात्र 10 प्रतिशत है जिसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की जरूरत है। तभी सहकारिता आंदोलन में नई ऊर्जा, नवाचार और स्थायी विकास संभव हो पाएगा। नेतृत्व स्तर पर तो युवाओं की भागीदारी नाममात्र है। कोऑपरेटिव सोसायटीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सहित अन्य पदों के लिए होने वाले चुनाव में युवाओं के लिए सीट आरक्षित कर और चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के लिए उम्र सीमा तय कर युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।

एनवाईसीएस के इन्वेस्टर मीट का आयोजन

युवा सहकार टीम

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) की चंड़ीगढ़ यूनिट द्वारा 72वें ऑल इंडिया सहकारिता सप्ताह के तत्वाधान में इन्वेस्टर मीट का आयोजन लॉ भवन, चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में एनवाईसीएस की उपबल्धियों पर प्रस्तुति दी गई और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेमजी गोयल ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से समृद्धि लाने का जो नारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिया है उससे भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूती मिल रही है। भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। सरकार ने सहकारिता के माध्यम से देश को सशक्त बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं उससे भारत अब सोने के शेर का रूप ले रहा है जो भविष्य में वैश्विक स्तर पर दहाड़ेगा।

एनवाईसीएस के प्रेसीडेंट प्रकाश चंद्र साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कोऑपरेटिव मिशन का संचालन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। सहकारिता क्षेत्र को अभूतपूर्व पहचान देने के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया है जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। एनवाईसीएस के कोऑपरेटिव मिशन को और गति देने के लिए चंडीगढ़, हरियाणा एवं पंजाब से आए निवेशकों एवं ऋणधारकों का आह्वान करते हुए उन्होंने जन निधी का तन, मन, धन से साथ देने को कहा। इससे आसपास के क्षेत्रों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान होगा। जन निधी एनवाईसीएस की माइक्रो फाइनेंस इकाई है जिसके माध्यम से युवाओं और अन्य लोगों को उद्यमी बनने एवं स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है।

कार्यक्रम की शुरूआत में पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह ग्रेवाल ने सिखों के नौंवे गुरु श्री तेग बहादुर जी की 350 साला शहीदी माह पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि एवं हरियाणा के पूर्व एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि जन निधी में निवेशकों की राशि पूरी तरह से सुरक्षित है। यह पिछले 26 वर्षों से पूरे देश में कार्यरत है जो वित्तीय सुरक्षा का प्रतीक है।

एनवाईसीएस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम चंद्र कुलकर्णी ने एनवाईसीएस के मुख्य उद्देश्य एवं जन निधी के बारे में विस्तारपूर्वक बताते हुए कहा की सहकारिता के क्षेत्र में एनवाईसीएस एकमात्र मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी है जिसके पास पैन इंडिया लाइसेंस है। उन्होंने देशभर में एनवाईसीएस द्वारा चलाई जा रही गतविधियों से कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को अवगत करवाया। एनवाईसीएस के राष्ट्रीय निदेशक देविंदर सिंह ने जन निधी की चंडीगढ़ क्षेत्र में स्थापना से लेकर आज तक के अपने अनुभवो को साझा किया।

श्यामानंद जी महाराज ने अपने संबोधन में उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि आज पंजाब का युवा नशे में डूबा हुआ है। नशे के दलदल से उन्हें निकालना जरूरी है। कोऑपरेटिव के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों का विकास कर उन्हें इससे दूर किया जा सकता है। कोऑपरेटिव वह ब्रह्मास्त्र है जिससे अत्यधिक विकास हो सकता है।

इस दौरान एनवाईसीएस की सक्सेज स्टोरीज का प्रदर्शन वीडियो के माध्यम से किया गया। इसे देखकर सभागार तालियों से गूंज उठा। साथ ही सभी सहयोगियों एवं समाज सेवी संस्थाओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर चंडीगढ़ नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर डॉ. हिमांशु गुप्ता मौजूद रहे। ■

राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी

भारत के लिए गौरव के साथ चुनौती

सत्येन्द्र पाल सिंह

दो दशक बाद राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में होंगे। भारत दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2010 का राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 26 नवंबर को ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में राष्ट्रमंडल खेल आम सभा की बैठक में अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में चुना गया। भारत को राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी संस्करण की मेजबानी की औपचारिक स्वीकृति मिलना पूरे देश के लिए गौरव के साथ चुनौती व जिम्मेदारी भी है। अगले राष्ट्रमंडल खेल में 15-17 खेल शामिल होंगे। इसके तहत एथलेटिक्स, तैराकी, मुक्केबाजी, नेटबॉल जैसे खेल पहले ही तय किए जा चुके हैं। खेलों की पूरी सूची 2026 के शुरू में जारी किए जाने की उम्मीद है।

भारत (अहमदाबाद) और नाइजीरिया (अबुजा) दोनों ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाई थी। भारत की कोशिश 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की भी है। उसके लिए भी अहमदाबाद प्रमुख दावेदार है। अहमदाबाद में इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है। भारत को 2030 के शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान घोषित किया जाना उसकी खेल यात्रा का खास पल है। 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित की गई थी। 2030 में इसके 100 साल पूरे होने का यह प्रतीकात्मक संस्करण होगा। यह मेजबानी बताती है कि वैश्विक समुदाय भारत को अहम आयोजनों के लिए सबसे काबिल देश मानता है। भारत की तेजी से बढ़ती वैश्विक आर्थिक रैंकिंग और मजबूत राजकोषीय स्थिति ने देश के इतिहास में खेलों में इतने बड़े निवेश को मुमकिन बनाया।

अहमदाबाद को अक्टूबर में ही राष्ट्रमंडल खेल के मेजबान शहर के रूप में नामित किया गया था। अब इसे औपचारिक रूप से मेजबान घोषित किया गया है। अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में नामित किए जाने की प्रक्रिया

भारत में दूसरी बार होंगे राष्ट्रमंडल खेल, अहमदाबाद है मेजबान शहर, 2010 में नई दिल्ली में हुआ था आयोजित

2030 का राष्ट्रमंडल खेल है इसका शताब्दी संस्करण, 1930 में पहली बार कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था आयोजन

का संचालन राष्ट्रमंडल खेल मूल्यांकन समिति ने किया था। समिति ने इसकी मेजबानी के दावेदार शहरों का मूल्यांकन कई मानकों पर किया, जिनमें खिलाड़ियों का अनुभव, बुनियादी ढांचा, तकनीकी क्षमता, सुशासन और मूल्यों के साथ सामंजस्य शामिल थे। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले ही 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप फाइनल का कामयाब आयोजन कर चुका है। जबकि सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव के तहत तैराकी सेंटर, फुटबॉल स्टेडियम और इंडोर एरीना बनाए जा रहे हैं।

भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी मिलने पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ठीक ही कहा कि भारत की मेजबानी की क्षमता इसके रिकॉर्ड से ही साफ हो जाती है। भारत ने 20 से ज्यादा शहरों में 22 अंतरराष्ट्रीय खेलों का कामयाब आयोजन किया है। इसमें पुरुष हॉकी विश्व कप, चेस ओलंपियाड, फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप, आईसीसी पुरुष और महिला क्रिकेट विश्व कप व विश्व पैरा एथलेटिक्स शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में 2002 में किया था। तब उसने 30 स्वर्ण सहित कुल 69 पदक जीते थे। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरूआत 1930 में हुई थी और 2030 में इसका 24वां संस्करण होगा। पिछला संस्करण 2022 में बर्मिंघम (ब्रिटेन) में हुआ था जिसमें टी20 क्रिकेट को शामिल किया गया था, लेकिन तब केवल महिलाओं की ही क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अगला संस्करण 2026 में ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में होगा। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीते थे।

भारत ने 2010 में जब नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी तब देश के प्रदर्शन के लिहाज से सबसे कामयाब रहा था। 2010 में भारत 38 स्वर्ण सहित कुल 101 पदक जीत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। इन खेलों में केवल इसी संस्करण में भारत ने 100 से अधिक पदक जीते हैं। बदकिस्मती से 2010 के राष्ट्रमंडल खेल की चर्चा मैदान पर भारत के कामयाब प्रदर्शन से ज्यादा इसमें तब हुए भ्रष्टाचार, समय पर कार्य न होना, बेवजह जरूरत से खर्च, आयोजन स्थलों पर घटिया सामानों की आपूर्ति की वजह से ज्यादा हुई, जो आज भी भारत के माथे पर कलंक की तरह है। बेशक इससे सबक लेकर 2030 में भारत साफ सुथरे आयोजन के संकल्प के साथ उतरेगा। वैसे भी भारत 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की कोशिश में है। ऐसे में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के कामयाब आयोजन को भारत बेताब होगा।

इतने विशाल खेल आयोजनों पर आने वाली लागत को आलोचक फिजूलखर्ची बताते हैं। इसकी बजाय वे इस खर्च को विकास योजनाओं पर लगाना किसी भी देश के लिए बेहतर विकल्प मानते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों, क्रिकेट विश्व कप और ओलंपिक की मेजबानी पर बेशक अरबों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन इससे मेजबान देश के लिए बड़े स्तर पर कारोबार और रोजगार का भी सृजन होता है। देश को अपनी सांस्कृतिक विरासत की बानगी दिखाने का भी मौका मिलता है। ऐसे में भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का कामयाब आयोजन करता है तो दुनिया को यह बताने में सफल रहेगा कि वह 2036 के ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन की सामर्थ्य रखता है। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल का कामयाब आयोजन कर भारत अपनी सांस्कृतिक ताकत, तकनीकी क्षमता, सांस्कृतिक विविधता और प्रशासनिक कौशल की बानगी दुनिया को दिखा सकता है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 में बतौर मेजबान भारत को दो नए या पारंपरिक खेल जोड़ने का भी अवसर मिलेगा। इसमें खेलों की संख्या 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों से जरूर ज्यादा होगी। भारत का सियासी व खेल नेतृत्व देश में कई प्रमुख खेलों का आयोजन कर खेलों का मजबूत राष्ट्रीय ढांचा बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के मायने हैं देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती।

गुजरात के प्रधान सचिव (खेल) अश्विनी कुमार कहते हैं, 'दुनिया में अब तक हुए राष्ट्रमंडल खेलों के अन्य संस्करणों से हमने सीख ली है। हम 2030 राष्ट्रमंडल खेल को बजट सीमा में सफल कार्यक्रम बनाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ज्यादातर स्थलों का निर्माण पूरा है और कुछ स्पर्धाएं तो चाहे आप आज ही करा लें। अहमदाबाद में दो बड़े खेल परिसर- सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव और पुलिस अकादमी स्पोर्टस एनक्लेव तैयार हो रहे हैं। इसलिए कोई समस्या नहीं होगी।' गुजरात सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हासिल कर अपना पहला सपना पूरा कर लिया है। अब अहमदाबाद ने ओलंपिक 2036 के लिए भी अपनी दावेदारी की है। ■

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये लेखक के अपने विचार हैं।)

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

SERVING **FARMERS**
TO GROW BOUNTIFUL

KRIBHCO world's premier fertilizer producing cooperative has been consistently making sustained efforts towards promoting modern agriculture and cooperatives in the country. It helps farmers maximize their returns through specialised agricultural inputs and other diversified businesses.

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD

Registered Office: A-60, Kailash Colony, New Delhi-110048 | **Phone: 011-29243412**
Corporate Office: KRIBCHO BHAWAN, A 8-10, Sector-1, Noida-201301, Distt: Gautam Budh Nagar (UP) | **Phones:** 0120-2534631/32/36
Website: www.kribhco.net | **KRIBCHO Kisan Helpline:** 0120-2535628 | **E-mail:** krishipramarsh@kribhco.net

OUR PRODUCTS

Neem Coated Urea | DAP | MOP | NPK | NPS | MAP | Liquid Bio Fertilizers | Certified Seeds | Hybrid Seeds
City Compost | Zinc Sulphate | Natural Potash | Sivarika | Rhizosuper

NYCS

National Yuva Co-operative Society Limited

Empowering Financial Independence

Our Services

Loans: Small, medium, and large loans at highly competitive interest rates, catering to the diverse financial needs of our members.
Deposits: Attractive interest rates, with special benefits for senior citizens and women.
Simplified Process: Our streamlined application process and flexible terms ensure that financial assistance is always within reach.

Our Reach

- Presence in All States & Union Territories
- 37 Branches Nationwide
- 600+ Districts Served by Our Representatives
- Central Administration Office (CAO) in Pune, Led by Senior Banking & Finance Professionals

Why Choose NYCS Ltd.?

- **Trusted Expertise** – Over 20 years in financial services.
- **Nationwide Presence** – A rapidly growing network.
- **Member-Focused** – Tailored financial solutions.
- **Youth Empowerment** – Supporting young entrepreneurs.

Contact Us

209, 2nd Floor, A2B, Vardhman Janak Market, Janakpuri, New Delhi-58
+91 9205595944
011-45096652/40153681
nycs.ltd@gmail.com
www.nycsltd.com

Together, let's build a brighter financial future!